

सोच से सफलता: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क्षेत्र में यूपी की नई उड़ान

योगी सरकार का लक्ष्य, 2030-31 तक 500 से अधिक जीसीसी स्थापित करेंगे

● जीसीसी पॉलिसी के जरिए निवेश आकर्षित कर रही योगी सरकार, 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित निवेश पाइपलाइन

● शैक्षणिक संस्थानों से साझेदारी और ग्लोबल कंपनियों की सहभागिता से तैयार हो रहा टेक्नोलॉजी एवं रोजगार का नया इको सिस्टम

यूपी की भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति केवल इस बात से तय नहीं होती कि यहां कितने उद्योग स्थापित हुए या कितना निवेश आया, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वह भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह कितनी मजबूती से बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयास इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं। सरकार की मंशा प्रदेश को केवल मैन्युफैक्चरिंग और पारंपरिक उद्योगों तक सीमित रखने की नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने की है। इस लक्ष्य के पीछे योगी सरकार की नीयत स्पष्ट है, पॉलिसी तैयार है और उसके अनुरूप नतीजे भी सामने आने लगे हैं।

नीयत: युवाओं को प्रदेश में ही ग्लोबल अवसर उपलब्ध कराना

2017 से पहले उत्तर प्रदेश बेरोजगारी का चरम और उद्योग-धंधों की बेहद खराब स्थिति झेल रहा था, जिसकी वजह से पलायन युवाओं की निर्यात बन चुका था। योगी सरकार की नीयत रही कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अवसरों के लिए दूसरे राज्यों या विदेश का रुख न करना पड़े। दुनिया की बड़ी कंपनियां प्रदेश में अपने ग्लोबल सेंटर स्थापित करें, यहां के युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करने का अवसर मिले और उत्तर प्रदेश की प्रतिभा वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 में वर्ष 2030-31 तक प्रदेश में 500 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा। प्रदेश में पहले से 200 से अधिक जीसीसी संचालित हैं। सरकार अब मौजूदा सेंटरों के विस्तार और नई वैश्विक कंपनियों के निवेश के माध्यम से इस संख्या को



बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऐसे सेंटर होते हैं, जहां से वे अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार के महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करती हैं। आज इनकी भूमिका बैंक ऑफिस और कस्टमर सपोर्ट से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक पहुंच चुकी है। ऐसे सेंटर उच्च कौशल वाले युवाओं को बेहतर रोजगार देने के साथ प्रदेश में आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच है कि प्रदेश की बड़ी युवा आबादी और प्रतिभाशाली मानव संसाधन को भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का व्यापक आधार और प्रतिवर्ष तैयार होने वाले दो लाख से अधिक एसटीआईएम स्नातक इस दिशा में बड़ी ताकत हैं।

नीति: जीसीसी पॉलिसी-2024 से निवेशकों को मिला प्रोत्साहन

नीयत को धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2024 तैयार की। इसका उद्देश्य प्रदेश को जीसीसी निवेश के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाना और कंपनियों को निवेश से लेकर संचालन तक विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। पॉलिसी के तहत पात्र परियोजनाओं को क्षेत्र के अनुसार 30 से 50 प्रतिशत तक लैंड सॉल्यूशंस का प्रावधान है। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 30 प्रतिशत, मथुरांचल और पश्चिमांचल के अन्य क्षेत्रों में 40 प्रतिशत



इससे निवेश को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने और क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

कैपिटल सॉल्यूशंस के तहत पात्र पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत तक सहायता का प्रावधान है। लेवल-1 जीसीसी के लिए यह अधिकतम 10 करोड़ रुपये और एडवांस्ड जीसीसी के लिए 25 करोड़ रुपये तक हो सकती है। पात्र इकाइयों को पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से इंटरेस्ट सॉल्यूशंस, अधिकतम एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल एक्सपेंस सॉल्यूशंस के तहत पांच समान वार्षिक किस्तों में 20 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है। लेवल-1 जीसीसी के लिए इसकी सीमा 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और एडवांस्ड जीसीसी के लिए 80 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक है। भूमि अथवा ऑफिस स्पेस की खरीद या लॉज पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट या प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय युवाओं को नियुक्त करने पर प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 1.8 लाख रुपये तक और अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए 1.2 लाख रुपये तक वेज सपोर्ट का प्रावधान है।

नतीजे: 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित निवेश पाइपलाइन

योगी सरकार की पॉलिसी के प्रति निवेशकों की बढ़ती रुचि अब निवेश पाइपलाइन में दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीसीसी पॉलिसी के तहत 30 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 24 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों और सक्रिय निवेश पाइपलाइन के आधार पर प्रदेश में 10 हजार करोड़

प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है। निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने भारत की शीर्ष 150 जीसीसी कंपनियों से संपर्क किया है। ये कंपनियां देश के लगभग 12 लाख जीसीसी प्रोफेशनल्स के कार्यबल के करीब दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं।

जीसीसी इनोवेशन समिट: 15 एमओयू और पांच निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट

26 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 इस दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। समिट में कंपनियों और टैलेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ 15 एमओयू किए गए तथा पांच निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए। ईवाई जीडीएस, एएमएल राइटसोर्स, कंप्यूटासेंटर, मेटलाइफ, डीएसवी, डैमैक, अल्ट्रास्ट और स्मार्टवर्क्स जैसी कंपनियों का सहभागिता प्रदेश में जीसीसी इकोसिस्टम के विस्तार की संभावनाओं को दर्शाती है। हैवेल्स इंडिया, अमेरिप्राइज इंडिया, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर, एलजी सॉफ्ट इंडिया और डब्ल्यूएसपी कंसल्टेंट्स इंडिया से संबंधित निवेश प्रस्तावों को भी लेटर ऑफ कम्फर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। एलजी सॉफ्ट इंडिया की प्रस्तावित परियोजना में लगभग 634 करोड़ रुपये के निवेश और 500 से अधिक रोजगार अवसरों की योजना है।

एआई, डीप टेक और बिजनेस पार्क: निवेश के लिए आधुनिक इकोसिस्टम
योगी सरकार की रणनीति जीसीसी को केवल बैंक ऑफिस या सर्विस डिलीवरी सेंटर तक सीमित रखने की नहीं है। समिट में एचसीएलटेक और आईआईटी कानपुर के डीप-टेक इनोवेशन कोलैबोरेशन के तहत तैयार श्वेत पत्र 'द टू इकोनॉमिक्स ऑफ एआई अडॉप्शन इन जीसीसी' का विमोचन इसी सोच का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिले। जीसीसी कंपनियों को विश्वस्तरीय ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए बिजनेस पार्क डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्थापित इकोसिस्टम के साथ सरकार लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में भी जीसीसी सेक्टर की संभावनाएं विकसित करना चाहती है। इससे निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक हो सकेगा।